अधिष्ठापित की जाती है, मिनी/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन में बढ़ौतरी किए जाने के लिए इस प्रकार की परियोजनाओं की लागत की 50 % तक की राशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है । यह आशा की जाती है कि समग्र देश में आठवीं योजना के दौरान मिनी/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं का विकास करके 1000 मेघावाट की अतिरिक्त क्षमता जोडी जा सकेगी । ऐसी परियोजनाओं के संबंध में राज्यवार लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इस प्रकार के क्रियाकलाप विभिन्न राज्यों में उपलब्ध शक्यता पर निर्भर करते है । इस समय देश में हिमालय के निकटवर्ती राज्यों में लघु जल विद्युत परियोजनायें (3 मे०वा० से 15 म०वा० तक की क्षमता वाली) निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं । इन परियोजनाओं में जोडे जाने वाली अतिरिक्त संभावित विद्युत उत्पादन क्षमता 97.25 मे.वा. होगी । इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है । **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) इस प्रकार की मिनी/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जो आर्थिक सहायता की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है इस प्रकार की सुविधा निजी क्षेत्र को परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई जाएगी बशर्ते इस प्रकार की मिनी/माइक्रो परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को मुख्यतः सार्वजनिक वितरण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ।

विवरण

हिमाचल पर्वत के निकटवर्ती राज्यों में निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं (3 मेघावाट से 15 मेघावाट तक की क्षमता वाली)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मेघावाट)
1.	चिरोट	हिमाचल प्रदेश	4.5
2.	बनर	हिमाचल प्रदेश	12
3.	गज	हिमाचल प्रदेश	10.5
4.	कारगिल	जम्मू व कश्मीर	3.75
5.	चेनानी 2 तथा 3	जम्मू व कश्मीर	6
6.	अटवाटू	जम्मू व कश्मीर	7.5
7.	सेवा–3	जम्मू व कश्मीर	6
8.	गोबला	उत्तर प्रदेश	6
9.	म्योंगचू	सिक्किम	4
10.	उत्तरी रोंगनीचू	सिक्किम	8
11.	नूरानांग	अरुणाचल प्रदेश	6
12.	लघु जल विद्युत	अरुणाचल प्रदेश	6
13.	डलाईमा	असम	6
14.	सेरलुई-ख	मिजोरम	9
		जोड :	97.25

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा मैथन परियोजना का निर्माण

4326. **श्री वीरेन जे. शाह :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा सोवियत संघ के सहयोग से मैथन राइट बैंक परियोजना का निर्माण करने के संबंध में निर्णय किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व सोवियत संघ के विराव के कारण परियोजना का कार्य अनिश्चितता की स्थिति में है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और इस परियोजना के निर्माण पर निगम द्वारा अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों पर दामोदर घाटी निगम की लेनदारी है ; और

(च) यदि हां तो सितम्बर, 1992 तक किस किस राज्य विद्युत बोर्ड पर कितनी-कितनी लेनदारी थी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) 4×210 मेगावाट (चरण I) ताप विद्युत परियोजना को 1205.08 करोड रुपए की अनुमानित लागत से अधिष्ठापित किए जाने के लिए परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) द्वारा नवम्बर 1988 में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया था ।

(ग) रूसी फडरेशन की सरकार ने राज्य से राज्य के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाने के बारे में सूचित किया है लेकिन इससे संबंधित शर्तों के लिए बातचीत की जानी है ।

(ग) परियोजना के लिए अपेक्षित निधियां अभी सुनिश्चित की जानी हैं । इस परियोजना के प्रारम्भिक कार्यों के लिए दामोदर घाटी निगम (डी वी सी) ने अभी तक 2.07 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ।

(ङ) और (च) 30 सितम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार दामोदर घाटी निगम की राज्य बिजली बोर्डों की ओर बकाया राशियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

राज्य बिजली बोर्ड	राशि (करोड रुपए)
1. पश्चिम बंगाल	115.64
2. बिहार	477.56
3. असम	0.15

दुल हस्ती जल विद्युत परियोजना के निर्माण में विलम्ब के कारण इसकी निर्माण लागत में वृद्धि

4327 **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठ मलानी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में दुल हस्ती जल विद्युत परियोजना मूल निर्धारित अवधि में पूरी न हो पाने के कारण, इसकी निर्माण लागत में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली बिजली की कीमत इतनी अधिक है कि यह परियोजना अनार्थिक बन गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और प्रारंभ में प्रति 1000 मेगावाट विद्युत की उत्पादन लागत क्या थी ; और

(ङ) क्या सरकार इस परियोजना के अनार्थिक होने संबंधी पहलू को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के स्वरूप पर पुनर्विचार करेगी, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) नैशनल हाइडो-इलक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, एन. एच.पी सी.) द्वारा दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना को तर्न-की आधार पर क्रियान्वित किए जाने के लिए सिम्तबर, 1989 में मसर्स सीईजीईएलईसी के नेतृत्व वाली एक फ्रांसीसी कन्सोर्टियम को ठेका दिया गया था । ठेके के अनुसार परियोजना को जुलाई, 1994 तक चालू किया जाना है । विगत के कुछ महिनों के दौरान परियोजना की प्रगति में अस्थायी गतिरोध उत्पन्न हो गया था । तथापि, परियोजना के पूरा होने के कार्यक्रम और लागत पर